

घोटाला और गबन में क्या अंतर है, गबन करने वाले कर्मचारी को दंड प्रावधान क्या है- CP Act, 1988

[The Prevention of Corruption Act, 1988 section 13]

घोटाला और गबन में अंतर होता है। यदि कोई अधिकारी किसी ठेकेदार को नियम विरुद्ध ठेका देता है तो इसे घोटाला कहेंगे लेकिन यदि वही अधिकारी मजदूरों को देने के लिए या सामान खरीदने के लिए निर्धारित शासकीय धन का व्यक्तिगत हित में खर्चा कर देता है, या फिर अपने अथवा किसी अन्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेता है। तब इसे गबन कहा जाएगा। यह भी कर्मचारी का भ्रष्ट आचरण है जिसके लिए उसे दंडित किया जाता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की परिभाषा: यदि किसी लोकसेवक को उसकी पदावधि के दौरान कोई शासकीय संपत्ति सौंपी गई है जो किसी सार्वजनिक कार्य या लोकहित के विकास के लिए उपयोगी है। उस संपत्ति को लोकसेवक अपने उपयोग के लिए बेईमानी से खर्च कर लेता है या उस संपत्ति को संपरिवर्तित (परिवर्तित) कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को शासकीय संपत्ति दे देता है तब ऐसा लोकसेवक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दोषी होगा।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान- यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होगा। इनकी सुनवाई विचारण का अधिकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम दस वर्षों की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

उद्धानुसार: ग्राम पंचायत में ग्राम विकास एवं मनरेगा के अंतर्गत मिले पैसे को सरपंच, सचिव बेईमानी एवं कपटपूर्ण तरीके से गबन कर लेते हैं तब दोनों अधिनियम की धारा 13 के अनुसार दोषी होंगे।

हेलियोन द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

नई दिल्ली।

कंज्यूमर हेल्थ में ग्लोबल मार्केट लीडर, हेलियोन ने आज भारत में अपनी पहली मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित करने की अपनी योजना के बारे में बताया। यह अत्याधुनिक फैक्ट्री पीथमपुर, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह फैक्ट्री भारत के कंज्यूमर हेल्थ सेक्टर में एक अहम निवेश होगी, जिससे एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में भारत के प्रति हेलियोन की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। इस निवेश की घोषणा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, श्री मोहन यादव, हेलियोन के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर, ब्रायन मैकनामारा, हेलियोन आईएससी के सीईओ इंडिया और अध्यक्ष- केदार लेले तथा हेलियोन की चीफ सप्लाय चैन ऑफिसर, नम्रता पटेल की मौजूदगी में की गई। यह निवेश भारत में हेलियोन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे सप्लाय चैन को और अधिक मजबूती मिलेगी, राष्ट्रीय आर्थिक मूल्यसंवर्धन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह निवेश भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप है। इससे अगले दशक में काफी अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त होगा। यह एक्सपोर्ट की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा, राज्य के राजस्व में योगदान देगा तथा भारत को ग्लोबल सप्लाय चैन में शामिल करेगा। इस फैक्ट्री से 500 से ज्यादा नौकरियों तक का निर्माण होने की उम्मीद है। साथ ही, अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। फैक्ट्री में कौशल विकास, स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा सप्लायर ईकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हेलियोन का उद्देश्य अपने



फैक्ट्री में एक व्यापक और समावेशी कार्यबल का निर्माण करना है, जिसमें कार्यबल में 30 प्रतिशत तक महिलाओं की भागीदारी हासिल करने की योजना है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कहा, “मध्य प्रदेश अपने मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुशल कार्यबल, और उद्योग के अनुकूल नीतियों के साथ ग्लोबल निवेश के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में लगातार उभर रहा है। हेलियोन द्वारा भारत में अपनी पहली मैनुफैक्चरिंग यूनिट पीथमपुर में स्थापित की जा रही है। यह निर्णय राज्य के बिजनेस इकोसिस्टम और विकास की क्षमता में बड़ी ग्लोबल कंपनियों का बढ़ता भरोसा प्रदर्शित करता है। 22,000 करोड़ के इस निवेश से मुख्य मैनुफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश की स्थिति मजबूत होगी। इससे आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में हेलियोन के विकास

में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सस्टेनेबल औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते रहेंगे।

हेलियोन के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर, ब्रायन मैकनामारा ने कहा, “भारत हमारे लिए सबसे तेजी से बढ़ते हुए और सबसे डायनामिक बाजारों में से एक है। यह इस बात की मिसाल पेश करता है कि हम मानवता पर केंद्रित रहते हुए किस प्रकार प्रतिदिन बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य साल 2030 तक प्रतिदिन बेहतर स्वास्थ्य को भारत में 30 करोड़ से अधिक नए ग्राहकों तक पहुंचाना है। हमारी यह फैक्ट्री साल 2030 तक हमें विश्व में 100 करोड़ नए ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह निवेश हमें अपने भरोसेमंद ब्रांड्स के लिए भविष्य की मांग को पूरा करने में समर्थ बनाएगा तथा हमारी जमीनी टीमों का विस्तार करेगा, ताकि हम उन करोड़ों लोगों को बेहतर पहुंच प्रदान कर सकें।

पत्नी अगर पति से घृणा करती है तो उसे साथ रहने विवश नहीं किया जा सकता, पढ़िए construction of india

वैसे तो पति-पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, कहते हैं स्वर्ग में बनता है एवं 7 जन्मों तक के लिए स्थाई होता है लेकिन बहुत से मामले कुटुम्ब न्यायालय में पत्नी द्वारा पति को तलाक देने के लिए लगाए जाते हैं। विवाद की स्थिति में याचिकाकर्ता को तलाक का आधार प्रमाणित करना पड़ता है लेकिन पत्नी के मामले में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि महिला को ऐसे पति के साथ रहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है जिससे वह घृणा करती है जानिए निर्णायक वाद।

प्रगति वर्गीज बनाम सिरिल जार्ज वर्गीज- मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10, 17, और 20 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इनसे महिलाओं के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त मानव गरिमा से जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। धारा 10 के अधीन एक ईसाई महिला को



लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

पति से तलाक लेते समय वरूता के साथ-साथ जारकर्म साबित करना भी एक अनिवार्य शर्त है जो प्रायः कठिन होता है। धारा 17 और 20 में यह नियम है कि जिला जज द्वारा तलाक का आदेश पारित किए जाने के पश्चात भी उच्च न्यायालय के 3 न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा उसकी पुष्टि

किया जाना अनिवार्य है।

न्यायालय द्वारा यह अधिनियमित किया कि धारा 10 पत्नी को ऐसे व्यक्ति (पति) के साथ रहने के साथ विवश करती है जिससे वह घृणा करती है, जिससे उसके साथ वरूता का व्यवहार करके उसे त्याग दिया था। ऐसा जीवन पशुवत जीवन है। वह ऐसे विवाह को विच्छेद करने के अधिकार को इन्कार करता है, जो विवाह असुधार्य टूट गया है। विवाह विच्छेद कराने के अधिकार को इन्कार करना अनुच्छेद 21 के अधीन प्राप्त प्राण के अधिकार का उल्लंघन है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन होता है जो महिलाओं के प्रति विभेदकारी है।

6उपर्युक्त मामले से स्पष्ट है कि महिलाओं को कोई भी कानून ऐसे पति के साथ रहने के लिए विवश नहीं कर सकता है जिससे वह घृणा करती है या ऐसा पति जो महिलाओं के साथ वरूता, अत्याचार आदि करता हो।

“

ED, CBI, सत्ता का डर दिखाया जा रहा है, भगत सिंह की विचारधारा को दबाया जा रहा है।

सोचो, उस दौर में हुकूमत कितनी घबराई होगी, जब एक नौजवान से पूरी सल्तनत थराई होगी।

आज भी उनकी विचारधारा से जो काँपते नज़र आते हैं, वे अनजान हैं कि आज भी भगत सिंह के वारिस ज़िंदा हैं।

”

- सोनू नोनेरिया



ग्राम बसरोही रैदासपुरा की जमीन पर भू-माफियाओं की नज़र 50-60 लोगों के जमीन नापने आने पर मड़के ग्रामीण, किया जटाशंकर रोड जाम

तहसील कार्यालय में एसडीएम ने नहीं सुनी समस्या, भारी विरोध के बाद तहसीलदार ने दिया 15 दिन में निराकरण का आश्वासन

बिजावर, छतरपुर।

ग्राम पंचायत एरोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसरोही (रैदासपुरा) की शासकीय भूमियों पर स्थानीय दलालों और भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे और बिक्री का खुला प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का आक्रोश तब फूट पड़ा जब भुवर कुआँ गाँव के करीब 50 से 60 लोग गाँव की सरकारी जमीन को देखने और नापने के लिए पहुँच गए। इस खुलेआम अतिक्रमण और दलाली से आक्रोशित होकर समस्त ग्रामवासियों ने लामबंद होकर आज जटाशंकर रोड पर चक्काजाम कर अपना विरोध दर्ज कराया। सड़क जाम होने के बाद मौके पर पहुँचे पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाव देकर तहसील कार्यालय जाने का अनुरोध किया। न्याय की गुहार लगाते हुए भारी संख्या में ग्रामीण

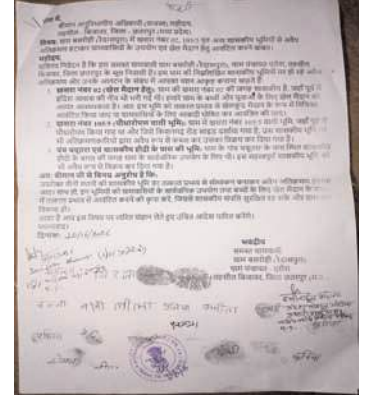


बिजावर तहसील कार्यालय पहुँचे और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान बिजावर एसडीएम महोदय वहाँ आए तो जरूर, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को दरकिनार कर दिया और उनकी बात नहीं सुनी। प्रशासन के इस रवैये से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया। लगातार हो रहे भारी विरोध और प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए अंततः तहसीलदार महोदय ने ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने



ग्रामवासियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और यह आश्वासन दिया कि आगामी 15 दिनों के भीतर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने और आवंटन की प्रक्रिया का विधिवत निराकरण कर दिया जाएगा। **ग्रामीणों की प्रमुख मांगें-** ग्राम की शासकीय जमीनों (विशेषकर खसरा नं. 02, 105/5 आदि) को दलालों के चंगुल से मुक्त कराकर अवैध कब्जा तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

उक्त भूमियों को गाँव के बच्चों एवं युवाओं के लिए %खेल मैदान% और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए विधिवत आवंटित किया जाए। ग्रामवासियों ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर दलालों के हाथों नहीं बिकने देंगे। यह लड़ाई गाँव के भविष्य, बच्चों के शारीरिक विकास और सरकारी जमीन को बचाने की है। ग्रामीणों ने कहा कि वे प्रशासन के 15 दिन के आश्वासन पर पूरी



नज़र बनाए रखेंगे। यदि समय सीमा के भीतर प्रशासन द्वारा ठोस और उचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ग्रामीण आगे भी उग्र जन-आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जब तक गाँव को उसका हक नहीं मिल जाता, यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने किए जाएं ठोस प्रयास-कलेक्टर

जिला कौशल समिति की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश



कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

कलेक्टर स्थित नर्मदा सभागार में मंगलवार को आयोजित जिला कौशल समिति की बैठक में कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल युवाओं को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें शत-प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तरह उद्योगों की वर्तमान मांग के अनुरूप हो, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को कंपनियों सीधे रोजगार देने के लिए तैयार रहें। बैठक में जिले में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिकीकरण का उल्लेख करते हुए कलेक्टर ने कहा कि एसईसीएल, मोजर बेयर, अडानी ग्रुप तथा टोरेन्ट पॉवर जैसी कंपनियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को उनकी पात्रता के अनुसार विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के तहत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें भविष्य में स्थायी रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। साथ ही, पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूलकिट

वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में आयोजित होने वाले युवा संगम रोजगार मेला का दायरा बढ़ाया जाए। विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मेले से जोड़कर उनका चयन सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें निजी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही जिले में स्थापित हो रही नई कंपनियों में भर्ती के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। कलेक्टर ने कोर्स डिजाइनिंग में बदलाव पर भी जोर देते हुए कहा कि जिले की भौगोलिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं। आधुनिक और तकनीकी ट्रेडों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से जुड़े सभी विभागों का एकमात्र लक्ष्य जिले के बेरोजगार युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना होना चाहिए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी सहित जिला कौशल विकास समिति के समस्त सदस्य उपस्थित रहे।

कुदरी पंचायत में सामाजिक न्याय की गुहार-कैलाश अहिरवार ने छेड़ी मुहिम, आगामी चुनाव में स्पष्ट वर्ग को मिले नेतृत्व का अधिकार

राजू राय / राहडोल।

जनपद पंचायत जयसिंहनगर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुदरी में आगामी पंचायत चुनाव और परिसीमन को लेकर जमीनी स्तर पर सरगमियां तेज हो गई हैं। पिछले दशकों से विकास की मुख्यधारा में अपनी सही भागीदारी तलाश रहे अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अधिकारों को लेकर अब क्षेत्र में एक बड़ी वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई है। क्षेत्र के प्रखर, समर्पित और लोकप्रिय युवा समाजसेवी कैलाश कुमार अहिरवार ने इस गंभीर मुद्दे पर एक मजबूत मुहिम छेड़ दी है। इस मुहिम के तहत ग्राम पंचायत कुदरी के समस्त ग्रामीणों ने एकजुट होकर राहडोल कलेक्टर को एक औपचारिक आवेदन पत्र सौंपा है। ग्रामीणों की मांग है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और आरक्षण चक्रानुक्रम (Rotation) नियम के तहत आगामी चुनाव में सरपंच पद की सीट अनुसूचित जाति (स्ट) के लिए आरक्षित की जाए। कई वर्षों से एक ही वर्ग के पास नेतृत्व, रोटेशन नियम लागू करने की मांग कलेक्टर महोदय को सौंपे गए आवेदन के अनुसार, ग्राम पंचायत कुदरी में पिछले 25 वर्षों (वर्ष 2000 से अब तक) से सरपंच का पद लगातार एक ही वर्ग (अनुसूचित जनजाति - ST) के लिए आरक्षित चला आ रहा है। वर्ष 2000 से 2005 तक दलेल सिंह, 2005 से 2010 तक मोती लाल सिंह, 2010 से 2015 तक बिट्टी बाई, 2015 से 2022 तक पुनः दलेल सिंह और वर्तमान में चंद्रवती सिंह इस पद पर दायित्व निभा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की है। इतनी बड़ी संख्या होने



के बावजूद चक्रानुक्रम नियम का पालन न होने से इस वर्ग को पिछले कई वर्षों से नेतृत्व करने का एक भी अवसर नहीं मिला है, जिससे समाज का सर्वांगीण उत्थान प्रभावित हो रहा है। विकास की गति ठप, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही जनता युवा समाजसेवी कैलाश कुमार अहिरवार ने पंचायत में विकास की जमीनी हकीकत को उजागर करते हुए कहा कि एक ही प्रशासनिक ढर्रे के कारण क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ चुके हैं और व्यवस्था में पारदर्शिता का घोर अभाव है। आज भी पंचायत के पास खुद का कोई सार्वजनिक सामुदायिक भवन नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को शादी-ब्याह या अन्य सामाजिक आयोजनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश मोहल्लों में पक्की पीसीसी (PCC) सड़कें न होने के कारण लोग कीचड़ और बदहाली के बीच जीने को मजबूर हैं।

नियमित और पारदर्शी ग्राम सभाएं न होने से जनता की आवाज दब कर रह गई है। हमारा उद्देश्य किसी व्यवस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि हर वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाना है। अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और उनके हक के लिए मैं हमेशा मजबूती से खड़ा रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। जब तक कुदरी पंचायत में बुनियादी ढांचा सुदृढ़ नहीं होता और पारदर्शिता नहीं आती, हमारी यह न्यायपूर्ण मुहिम जारी रहेगी। कैलाश कुमार अहिरवार (युवा समाजसेवी) निष्पक्ष जांच और सामाजिक न्याय की गुहार कैलाश कुमार अहिरवार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि ग्राम पंचायत कुदरी की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आगामी परिसीमन में सरपंच पद %अनुसूचित जाति% के लिए आरक्षित किया जाए। इसके साथ ही, विगत वर्षों में पंचायत के विकास कार्यों के नाम पर हुए खर्चों की एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके और क्षेत्र का वास्तविक विकास हो सके। युवा नेतृत्व की इस सकारात्मक पहल और सामाजिक न्याय की इस मुहिम को क्षेत्र के युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों का भारी समर्थन मिल रहा है।

नगर परिषद डोला के 7 से 8 लाख रुपए की जिम के समान 2 साल के अंदर ही क्षतिग्रस्त इन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

राजनगर। अनूपपुर जिले के नगर परिषद डोला द्वारा जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगभग दो वर्ष पूर्व लाखों रुपये की लागत से लगाए गए ओपन जिम उपकरण अब भ्रष्टाचार की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने स्थापित जिम उपकरणों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कई झूले टूट चुके हैं, रंग उखड़ गया है और लोहे की पाइपों में जंग लगने लगी है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद ये उपकरण इतनी जल्दी कबाड़ में कैसे तब्दील हो गए?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन जिम उपकरणों की गुणवत्ता शुरू से ही बेहद खराब थी। कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद न तो मरम्मत कराई गई और न ही जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेना उचित समझा। नगर परिषद कार्यालय के सामने लगे इन उपकरणों की बदहाली यह साबित करती है कि जिम्मेदारों की नजर सब कुछ देखकर भी अनदेखा करने में लगी हुई है।



जनता का आरोप - परिषद में विकास नहीं, भ्रष्टाचार का खेल क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर परिषद में इन दिनों विकास कार्यों से ज्यादा चर्चा कमीशन और ठेकेदारी की हो रही है। लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी खुद ही सामग्री चयन से लेकर कार्यों की निगरानी तक में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे गुणवत्ता पूरी तरह प्रभावित होती है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि यदि लगभग 7 से 8 लाख रुपये की लागत से लगाए गए जिम उपकरण दो साल भी नहीं टिक पाए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्यों में किस स्तर की सामग्री उपयोग की गई होगी। जनता का सवाल है कि आखिर ऐसे कार्यों की तकनीकी जांच

क्यों नहीं होती और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी?

सीएमओ बोले - जानकारी नहीं थी जब इस संबंध में नगर परिषद डोला के सीएमओ से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उपकरण क्षतिग्रस्त हैं तो वे उन्हें दिखावा लेंगे। हालांकि उन्होंने किसी प्रकार की जांच या जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात नहीं कही।

सीएमओ का यह जवाब भी कई सवाल खड़े करता है। नगर परिषद कार्यालय के सामने लगे जिम उपकरण महीनों से बदहाल हैं, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।



कार्यालय के सामने ही बदहाली, फिर भी मौन जिम्मेदार

सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन जिम उपकरणों की हालत खराब हुई है, वे नगर परिषद कार्यालय के सामने ही स्थापित हैं। यानी अधिकारी और जनप्रतिनिधि रोजाना इनकी स्थिति देखते होंगे, लेकिन सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जनता पूछ रही है कि यदि नगर परिषद कार्यालय के सामने लगे सार्वजनिक संसाधनों की यह स्थिति है तो दूरस्थ वाडों में किए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

जनता के सवाल



7 से 8 लाख रुपये की लागत वाले जिम उपकरण दो साल में ही क्यों टूट गए? क्या निर्माण और खरीद प्रक्रिया की जांच होगी?

घटिया सामग्री उपयोग करने वालों पर कार्रवाई कब होगी?

नगर परिषद कार्यालय के सामने बदहाल पड़े उपकरणों की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल नगर परिषद डोला के इन जर्जर जिम उपकरणों ने विकास कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

सीमा पार से रेत तस्करी पर खनिज विभाग का शिकंजा, बिना नंबर की डगगी जब्त

छत्तीसगढ़ से अवैध रेत लाने की मिल रही थीं शिकायतें, कार्रवाई में खुली पोल

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

जिले में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबर की डगगी वाहन को जब्त किया है। लंबे समय से मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे क्षेत्रों में अवैध रेत परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के बाद खनिज विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया, जिसमें एक संदिग्ध डगगी वाहन रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया।

शनिवार रात रामनगर क्षेत्र में चलाए गए सघन जांच अभियान के दौरान खनिज निरीक्षक ईशा वर्मा ने बिना नंबर की डगगी वाहन को रोककर जांच की। जांच में रेत परिवहन पूरी तरह अवैध पाए जाने पर खनिज अमले ने तत्काल वाहन को जब्त कर रामनगर थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया।

बिना नंबर की गाड़ी ने खड़े किए कई सवाल
कार्रवाई के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वाहन पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बिना नंबर का वाहन सड़कों पर कैसे दौड़ रहा था? स्थानीय लोगों का कहना है कि



नंबर प्लेट का न होना यह संकेत देता है कि वाहन लंबे समय से अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा होगा और पहचान छिपाने के उद्देश्य से नंबर नहीं लगाया गया होगा। क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि सीमावर्ती इलाकों से रेत का अवैध परिवहन कोई नई बात नहीं है। यदि खनिज विभाग की कार्रवाई में एक वाहन पकड़ा गया है तो यह केवल एक कड़ी हो सकती है। सवाल यह भी है कि क्या इस अवैध कारोबार के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिसकी जांच की आवश्यकता है।

खनिज विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति



उप संचालक खनिज श्रीमती आशालता वैद्य ने बताया कि कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देश पर जिलेभर में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जब्त वाहन के खिलाफ मध्यप्रदेश खनिज (अवैध परिवहन) नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनिज परिवहन, ओवरलोडिंग और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रशासन की 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी और भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे।

अब जांच बड़े नेटवर्क तक पहुंचेगी या नहीं?

खनिज विभाग की इस कार्रवाई ने एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित अवैध रेत कारोबार की ओर ध्यान खींचा है। जनता की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या जांच केवल वाहन जब्ती तक सीमित रहेगी या फिर अवैध रेत परिवहन के पूरे नेटवर्क और उसके संरक्षकों तक भी पहुंचेगी। फिलहाल, बिना नंबर की डगगी पर हुई कार्रवाई ने यह जरूर साबित कर दिया है कि सीमा पार से अवैध रेत परिवहन की शिकायतें निराधार नहीं थीं, बल्कि जमीनी हकीकत अब सरकारी कार्रवाई में भी सामने आने लगी है।

पुरुषोत्तम माह में ग्राम कोड़ा जमुनिया में श्रीरामचरितमानस पाठ का भव्य आयोजन



हल्केवीर सूर्यवंशी
संभागीय संवाददाता

देवरी /रायसेन- ग्राम कोड़ा जमुनिया, तहसील देवरी स्थित खेरापति दरबार (एनएच-45) में पुरुषोत्तम माह के शुभ अवसर पर श्रीरामचरितमानस पाठ का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में ग्राम के सभी श्रद्धालु बड़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। साथ ही आसपास के गांवों के लोग भी अपनी सहभागिता और सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

आयोजन स्थल पर प्रतिदिन भगवान श्रीराम के भजनों, चौपाइयों एवं धार्मिक प्रवचनों से भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रतिदिन सायंकाल महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें ग्रामीणों एवं आगंतुक श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। आयोजन समिति के अनुसार श्रीरामचरितमानस पाठ का समापन पुरुषोत्तम माह की अमावस्या के दिन विधि-विधान के साथ किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में 'सद्भावना समिति' एवं ग्राम के समस्त नागरिकों का विशेष योगदान रहा है। ग्रामीणों ने सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है।

निवेदक: समस्त ग्रामवासी, कोड़ा जमुनिया तहसील देवरी, जिला रायसेन (मध्य प्रदेश)



छत्तीसगढ़ से मवेशियों की तस्करी पर रामनगर पुलिस का बड़ा प्रहार, 26 भैंसों मुक्त कराई गईं

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

राजनगर/रामनगर। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा से पशुओं की अवैध ढुलाई और वस्त्रता के खिलाफ रामनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 नग भैंसों को मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि मवेशियों को छत्तीसगढ़ से पैदल हांफते हुए कोतमा क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस ने जंगल क्षेत्र में घेराबंदी कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त मुराब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम एवं एसडीओपी कोतमा आरती शाक्य के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना रामनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में मवेशियों को वस्त्रता पूर्वक पैदल हांफकर ले जाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सुमित कौशिक के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल सक्रिय हुई और



टांकी जंगल क्षेत्र में दबिश देकर 26 नग भैंसों को जप्त कर लिया। जंगल के रास्ते हो रहा था परिवहन, पुलिस ने नाकाम की कोशिश जानकारी के अनुसार मवेशियों को मुख्य मार्गों से बचाते हुए जंगल के रास्तों से ले जाया जा रहा था। पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपियों की योजना सफल नहीं हो सकी और मवेशियों को समय रहते मुक्त करा लिया गया। जप्त सभी पशुओं को सुरक्षित रूप से कांजी हाउस मलगा में रखा गया है। मामले में आरोपी आनंद राम सिंह (49

वर्ष), पिता भोरेलाल सिंह, निवासी ग्राम मलगा, थाना रामनगर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 146/26 दर्ज कर पशु वस्त्रता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

'सूचना मिलते ही होगी कार्रवाई'
थाना प्रभारी सुमित कौशिक

इस संबंध में जब थाना प्रभारी सुमित कौशिक से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा



कि रामनगर पुलिस द्वारा लगातार पशु वस्त्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को पशुओं की अवैध ढुलाई, तस्करी या वस्त्रता से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।

थाना प्रभारी ने कहा, 'पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पशुओं के साथ किसी भी

प्रकार की वस्त्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी

रामनगर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय पशु तस्करी में हड़कंप मच गया है। पुलिस का मानना है कि अवैध पशु परिवहन और पशु वस्त्रता पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी और अभियान चलाए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ की सीमा से मध्यप्रदेश में प्रवेश करते ही हुई इस कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि पशुओं के साथ वस्त्रता करने वालों और अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस अब किसी भी कीमत पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है।

मंडलम कमेटी धरमी की बैठक संपन्न

जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा के निर्देशन में मंडलम कमेटी धरमी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों तथा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में हर्ष पर्यवेक्षक प्रशांत शर्मा, जिला प्रवक्ता चंद्रजीत सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हर्ष के अध्यक्ष रामजी उईके, सेवादल अध्यक्ष धनीराम भलावी, आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष नरथूलाल उईके, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सविता बरकडे, ब्लॉक उपाध्यक्ष पदमा डेहरिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकुमार सरेआम, नारायण इनवाती, मनीष डेहरिया, नरेश उईके सहित मंडलम कमेटी धरमी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ एवं पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दों को



लेकर सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर मंडलम क्षेत्र की समस्त माताओं, बुजुर्गों, युवा साथियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। बैठक का समापन कांग्रेस पार्टी को गांव-गांव तक मजबूत बनाने एवं जनसेवा के संकल्प के साथ किया गया।

सम्माननीय साथियों,
जय भीम! नमो बुद्धाय!

आप सभी को आमंत्रण देते हुए अत्यंत खुशी हो रही है की अहिरवार समाज संघ मध्य प्रदेश रजि.38053/2021 का प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 14/06/2026, दिन रविवार को आयोजित किया जा रहा है।

स्थान : आईटीआई सभा कक्ष, गोविंदपुरा, भोपाल (मध्य प्रदेश)

समय : प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

पांच दिवसीय गोंडी कोया पुनेम महोत्सव का भव्य समापन, धर्म-संस्कृति और समाज उत्थान पर दिया गया विशेष जोर

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा/नोनिया बरेली। पांच दिवसीय गोंडी कोया पुनेम महोत्सव का भव्य एवं गरिमामय समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लेकर गोंडी धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान धर्माचार्य तिरु. देवदास उईके जी ने अपने उद्बोधन में गोंडी धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनके विचारों ने उपस्थित समाजजनों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मुख्य अतिथि राजा कुंवर धर्मवीर सिंह जी ने वर्ष 1778 से 1945 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने 9 जून को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया।

आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष तिरु. बैजनाथ उईके जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर शिक्षित एवं जागरूक समाज के निर्माण पर विशेष बल दिया। वहीं आदिवासी विकास परिषद (युवा प्रभाग) के जिलाध्यक्ष तिरु. कुंवर सूर्यजीत सिंह ने अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमंग सिंघार जी के मार्गदर्शन में जनगणना प्रपत्र में धर्म कोड की मांग को प्रमुखता से उठाने की बात



कही। कार्यक्रम में तिरु. पप्पू ठाकुर (चैनपुर) एवं तिरु. रामलाल धुर्वे (घूरपुर) सहित अन्य वक्ताओं ने भी समाजहित एवं संगठन की मजबूती को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। महोत्सव के दौरान बेटीयों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया, जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से

सराहना की। पांचों दिनों तक मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं युवाशक्ति की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।

समापन अवसर पर भावपूर्ण पुनेम सुमिरन किया गया तथा समाजजनों ने अपने-अपने इष्ट देवी-देवताओं को सेवा जौहार अर्पित कर प्रसादी ग्रहण की और अपने घरों के लिए रवाना हुए।

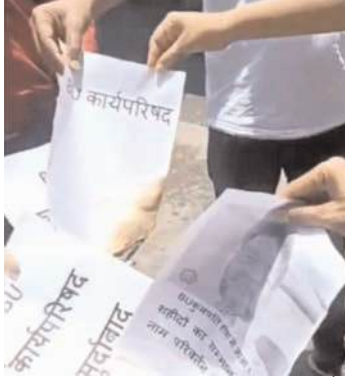
बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के प्रस्ताव पर फूटा छात्रों का गुस्सा

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने जोरदार प्रदर्शन कर BU कार्यपरिषद व कुलपति की छाया प्रति को जलाकर किया आक्रोश व्यक्त

महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की विरासत मिटाने की कोशिश : छात्र संगठन SFI

भोपाल।

बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय (BU) की कार्यपरिषद द्वारा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर %मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय% करने के प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद राजधानी भोपाल में छात्र राजनीति गरमा गई है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने इस फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में उग्र प्रदर्शन किया और कार्यपरिषद के इस निर्णय की कड़ी निंदा की। इतिहास से छेड़छाड़ और स्वतंत्रता सेनानी का अपमान छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद का यह फैसला एक महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की विरासत को मिटाने और इतिहास से छेड़छाड़ करने की एक



सोची-समझी राजनीतिक कोशिश है। संगठन के नेतृत्वकारी साधियों ने स्पष्ट कहा कि मौलाना बरकतुल्लाह ने देश की आजादी के लिए वैश्विक स्तर पर संघर्ष किया था, और उनके नाम को हटाना राष्ट्रभक्तों का अपमान है। छात्र संगठनों ने इस विवादित प्रस्ताव को तुरंत वापस



लेने की मांग की है।

बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश-प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीते लंबे समय से विश्वविद्यालय में कई बड़े घोटाले हुए हैं। इन घोटालों को छुपाने के लिए और प्रदेश सरकार व संघ की सांप्रदायिक नीति के इशारे पर नाम परिवर्तन की

राजनीति को हवा दी जा रही है।

SFI के प्रतिनिधियों ने कहा- 'यूनिवर्सिटी का नाम बदलना छात्रों का मूल प्रश्न नहीं है। आज छात्रों को बेहतर शिक्षकों, प्रोफेसर्स की जरूरत है। विभागों में अभी भी हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, जिस पर कार्यपरिषद का कोई ध्यान नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के द्वारा ऐसे गैर-जरूरी मुद्दों को उठाना,

जो सीधे तौर पर छात्रों की पढ़ाई से नहीं जुड़े हैं, पूरी तरह अनुचित है।' सांप्रदायिक और भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने कुलपति डॉ. सुरेश कुमार जैन और पूरी कार्यपरिषद की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि परिषद को छात्रों के जरूरी शैक्षणिक सवालों पर विचार करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा ऐसे गलत और राजनीति से प्रेरित प्रस्तावों को बढ़ावा देना निंदनीय है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का आम छात्र इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट है। यदि इस सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाले प्रस्ताव को तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो छात्र आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन और राष्ट्रव्यापी संघर्ष के लिए मजबूर होंगे।

NCC शिविर का भव्य समापन कैडेट्स ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन



मथुरा, 10 जून 2026, फरह, मथुरा।

10 यूपी बटालियन NCC, मथुरा द्वारा आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आज भव्य समापन हुआ। शिविर के अंतिम दिन कैडेट्स ने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बटालियन का नाम गौरवान्वित किया।

सुबह के सत्र में जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल (JD & FS) का डेमोस्ट्रेशन आयोजित किया गया। NCC कैडेट्स ने सटीकता और अनुशासन के साथ सेक्शन फॉर्मेशन और बैटल ड्रिल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का संयोजन ट्रेनिंग ऑफिसर द्वारा किया गया। कैप कमांडेंट ने सभी कैडेट्स को जजिंग डिस्टेंस एवं फील्ड सिग्नल



के व्यावहारिक महत्व और तकनीकों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शिविर का विधिवत समापन हुआ। मीडिया प्रभारी कैप्टन मनोरमा कौशिक ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में कैडेट्स ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, एकल गायन एवं नाट्य प्रस्तुतियों सहित विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय

एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट्स ने अपनी प्रतिभा से बटालियन को गौरवान्वित किया। समापन समारोह के अवसर पर कैप कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट एवं 10 यूपी बटालियन का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कैप कमांडेंट ने सभी कैडेट्स के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शिविर के सफल संचालन में सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

स्वतंत्र कलम से प्रभारी सीएमएचओ संजय रिषेश्वर की...

स्वतंत्र कलम से प्रभारी ससीएमएचओ संजय रिषेश्वर की यह कैसी जांच जिसकी शिकायत है उसको अभी तक वर्तमान पद से हटाया नहीं गया तो निष्पक्ष कैसे जांच होना होगी समाननीय सअर्पित तवर्मा जी सआईएसएस सकलेक्टर सजिला सशिवपुरी इस और विशेष ध्यान दें जिसकी शिकायत दर्जनों नहीं सेकड़ों है कई जांचों में दोषी है वर्तमान में आपके द्वारा सिविल सर्जन जिला शिवपुरी डॉक्टर बच्चन लाल यादव जी से जांच कराई जा रही है और

जहां से रिपोर्ट भी आपने शीघ्र मांगी है लेकिन हमें नहीं लगता की जांच सिलेबस होगी क्योंकि बच्चन लाल भी डॉक्टर है और संजय भी डॉक्टर है यह दोनों ही एक कहावत है ना चोर चोर मौसेरे भाई दोनों ही डॉक्टर है और एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी माननीय कलेक्टर महोदय आपको सबसे पहले प्रभारी सीएमएचओ संजय रसेश्वरी को पद से हटना चाहिए तभी कर्मचारी खुलकर और उसके खिलाफ बयान दे पाएंगे

शिवपुरी में चर्चा है की प्रभारी सीएमएचओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रूम को फोन लगाकर यह बोल रहा है कि किसी को बयान देने कर्मचारियों को नहीं आने देना है अब कर्मचारियों को नौकरी करना है तो फिर वह डर के कारण ध्यान भी नहीं दे पा रहे माननीय कलेक्टर महोदय सबसे पहले आपको प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर संजय ऋषिेश्वर को पद से हटाए तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है अल्फा जांच के नाम पर खाना पूर्ति होगी

कापी महंगी, पुस्तक महंगी, अउ महंगी स्कूल के फीस। गरीब छात्र के स्कूल ड्रेस मा, अब कैंची भी चला दीं।। सुसासन के ढोल बजावत, सांय-सांय वोहा रंगत है। बाद काफिला के गुजरे के, पीठ मा छूरा भोंगत है।। लक्ष्मी नारायण कुम्भकार सचेत दुर्ग (छठगठ)

नवभारत Bhopal City - 08 Jun 2026 - 08:00 AM
 दिवकत : नियम दो जोड़ी का, लगातार दूसरे साल स्कूली छात्रों के ड्रेस में कटौती

स्कूली ड्रेस में कटौती, गरीब बच्चों को दो की जगह मिलेगी एक जोड़ी!

सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए रहने के साथ एक मायूस करने वाली खबर है। 16 जून से स्कूल खुलने ही बच्चों को निराला युनिफॉर्म तो मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी उन्हें केवल एक जोड़ी ड्रेस से ही संतोष करना पड़ेगा। नियमानुसार बच्चों को दो जोड़ी ड्रेस मिलनी चाहिए, लेकिन इस सत्र में भी विभाग ने सीधे तौर पर 50 फीसदी की कटौती कर दी है। पिछले साल भी बच्चों को दो की जगह सिर्फ एक ही जोड़ी ड्रेस दी गई थी।

बच्चों को खरीदना पड़ेगा एक जोड़ी ड्रेस

एक मायूस करने वाली खबर है। 16 जून से स्कूल खुलने ही बच्चों को निराला युनिफॉर्म तो मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी उन्हें केवल एक जोड़ी ड्रेस से ही संतोष करना पड़ेगा। नियमानुसार बच्चों को दो जोड़ी ड्रेस मिलनी चाहिए, लेकिन इस सत्र में भी विभाग ने सीधे तौर पर 50 फीसदी की कटौती कर दी है। पिछले साल भी बच्चों को दो की जगह सिर्फ एक ही जोड़ी ड्रेस दी गई थी।

जून को स्कूल खुलने ही प्राइमरी और मिडिल के बच्चों को बांटे जाएंगे गणवेश

विभाग के इसकी खबर की यह खबर है। 16 जून से स्कूल खुलने ही बच्चों को निराला युनिफॉर्म तो मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी उन्हें केवल एक जोड़ी ड्रेस से ही संतोष करना पड़ेगा। नियमानुसार बच्चों को दो जोड़ी ड्रेस मिलनी चाहिए, लेकिन इस सत्र में भी विभाग ने सीधे तौर पर 50 फीसदी की कटौती कर दी है। पिछले साल भी बच्चों को दो की जगह सिर्फ एक ही जोड़ी ड्रेस दी गई थी।

ड्रेस पहना, स्कूल खुलने ही विभाग

विभाग के इसकी खबर की यह खबर है। 16 जून से स्कूल खुलने ही बच्चों को निराला युनिफॉर्म तो मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी उन्हें केवल एक जोड़ी ड्रेस से ही संतोष करना पड़ेगा। नियमानुसार बच्चों को दो जोड़ी ड्रेस मिलनी चाहिए, लेकिन इस सत्र में भी विभाग ने सीधे तौर पर 50 फीसदी की कटौती कर दी है। पिछले साल भी बच्चों को दो की जगह सिर्फ एक ही जोड़ी ड्रेस दी गई थी।

युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया

पत्रकार बीआर अहिस्वार नर्मदापुरम।

। शासकीय गृहविज्ञान स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय नर्मदापुरम द्वारा युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। रोजगार मेले में पुणे महाराष्ट्र से आठ कंपनियां सम्मिलित हुई एवं रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मोहासा औद्योगिक क्षेत्र नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल, बुधनी, अब्दुल्लागंज, मंडीदीप की कुल 34 कंपनियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति नीतू यादव, अपर कलेक्टर श्री ब्रजेंद्र रावत, जिला रोजगार अधिकारी श्री श्याम धुर्वे, शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नर्मदापुरम के प्राचार्य डॉ रामकुमार चौकसे, आई.टी.आई प्राचार्य श्री मरकाम ने मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने जिले के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह युवा



संगम युवाओं हेतु मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा आयोजित किया गया है जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार स्वरोजगार और इंटरशिप के अवसर उपलब्ध कराना एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं बैंक ऋण स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। अपर कलेक्टर श्री ब्रजेंद्र रावत ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमंत्रित कंपनियों द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का सृजन किया गया है जिससे अधिक से अधिक संख्या में इस युवा संगम का लाभ प्राप्त कर सकें। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ श्रीमती

कामिनी जैन ने बताया कि जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग से युवा संगम मेले का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों को कैरियर के विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देकर मार्गदर्शन प्रदान किया गया, रोजगार प्रदाता कंपनियों, उद्योगों एवं अन्य संस्थाओं को आमंत्रित कर विभिन्न सेवाओं में विद्यार्थियों का प्लेसमेंट कराने की व्यवस्था की गई एवं विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में संचालित प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के अंतर्गत इंटरशिप की जानकारी दी गई। मेले में विभिन्न स्वरोजगार और रोजगार से संबंधित कंपनियों के स्टॉल लगाए गए



जिसमें विद्यार्थियों द्वारा कैरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर क्षमता एवं योग्यता अनुसार रोजगार हेतु आवेदन किए गए। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की जिला नोडल अधिकारी डॉ संगीता अहिस्वार ने बताया कि रोजगार मेले में जिले के सभी युवा वर्ग सम्मिलित हुए हैं। युवाओं को सीधे कंपनी में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं एवं स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। महाविद्यालय की ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी डॉ रागिनी सिकरवार द्वारा रोजगार मेले में लगभग 300 पंजीयन हुए एवं छात्राओं को प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के अंतर्गत संचालित इंटरशिप

प्रोग्राम संचालित करने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी दी गई जिससे विद्यार्थी पोर्टल पर अपने जिले की संबंधित कंपनी में पंजीकरण कर सकें और इस योजना का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में जिला रोजगार कार्यालय के ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर धर्मे श तिवारी, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ भारती दुबे, डॉ हर्षा चचाने, डॉ कंचन ठाकुर एवं समस्त महाविद्यालयीन स्टॉफ उपस्थित रहे। मंच का सफल संचालन डॉ प्रगति जोशी ने एवं आभार प्रदर्शन डॉ रागिनी सिकरवार ने किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में जिले के समस्त महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सहभागिता की एवं रोजगार प्राप्त किये।

MP: 34 जिलों में तेज हवाओं और आंधी-तूफान की संभावना



कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ

प्रदेश - मध्य प्रदेश में मौनसून से पहले मौसम की गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी-तूफान और बारिश के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति एक ट्रफ (trough) और चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) सिस्टम के प्रभाव के कारण बनी है। इसके चलते आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम अस्थिर बना रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को जारी की गई चेतावनी में कहा कि राज्य के कुल 34 जिलों में 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान और बारिश हो सकती है। प्रभावित जिलों में ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, रायसेन,

नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, सतना, शहडोल, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी शामिल हैं। IMD के अनुसार, राज्य के मध्य और उत्तरी हिस्सों में हवा की गति तेज रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने और गरजने की घटनाएं भी हो सकती हैं। अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन और लोगों को सचेत रहने के लिए सलाह दी है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि इस अस्थिर मौसम के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं, विशेषकर खुले खेतों में काम करने वाले किसान जोखिम में रह सकते हैं। इसलिए सलाह दी गई है कि लोग आवश्यक सावधानियां अपनाएं और पेड़-पौधों और ढांचे को सुरक्षित रखें। IMD ने

बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण राज्य में मौसम अस्थिर हो गया है। ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे में स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहना होगा। ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में तेज हवाओं और बारिश के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और खुले स्थानों में कम रहने की सलाह दी है। इसके अलावा बिजली गिरने और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना बालिका इकाई द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस हर्ष और उल्लास से राष्ट्रीय सेवा योजना बालिका इकाई द्वारा मनाया



पत्रकार बीआर अहिस्वार नर्मदापुरम।

5 जून 20 26 को प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेस शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदा पुरम राष्ट्रीय सेवा योजना बालिका इकाई द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस हर्ष और उल्लास से राष्ट्रीय सेवा योजना बालिका इकाई द्वारा मनाया गया कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर इरा वर्मा ने बताया कि प्राचार्य डॉ रामकुमार चौक से के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों में पर्यावरण संवारने के विभिन्न उपायों की विवेचना की कार्यक्रम के प्रथम चरण में पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान का आयोजन भी किया गया जिसमें पर्यावरण बचाने के विभिन्न उपायों पर विद्वानों ने चर्चा की द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों ने रैली निकालकर पर्यावरण बचाने की जनता से अपील की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर इरा वर्मा ने स्वयंसेवकों से जमीन जंगल और जल बचाने की अपील की प्रत्येक विद्यार्थी को एक पौधा

लगाने की प्रेरणा की उन्होंने कहा हम यदि आज नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे हमें पर्यावरण बचाना होगा जिससे प्रकृति का हरियाली से श्रृंगार तो होगा मानव जीवन का भी विनाश होने से बचेगा हमें पर्यावरण जागरूकता का परिचय देते हुए पौधे लगाने होंगे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए स्वच्छ वातावरण स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना होगा जल का दुरुपयोग रोकना होगा नदियों में तालाबों में प्लास्टिक और गंदगी और कचरा घर का कचरा नहीं डालना होगा स्वच्छता का निर्माण भी करना होगा मानव जीवन बहुमूल्य है और हमें इसे जीने लायक बनाना है और उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जिससे हमें स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण जीने की परिस्थितियों उपलब्ध हो सके कार्यक्रम में महाविद्यालय के डॉक्टर रवि उपाध्याय डॉ राजेश दीवान डॉक्टर प्रीति उदयपुर डॉक्टर रीना सक्सेना डॉक्टर सविता आनंद डॉ महेंद्र तथा विद्यार्थी उपस्थित थे

नवीन छावनी पठार, रायसेन रोड भोपाल में हुआ बौद्ध विहार का उद्घाटन



नवीन छावनी पठार भोपाल।

विशेष प्रसन्नता की बात है कि दिनांक 07 जून 2026, दिन रविवार को नवीन छावनी पठार रायसेन रोड भोपाल में डॉ भीमराव अंबेडकर मंगल मैत्री बौद्ध विहार मोनेस्ट्री एवं धम्म प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। उद्घाटन ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि बिरू राजपूत, ग्राम पंचायत के सैंकड़ों गणमान्य नागरिक, पूज्य भंते संघ, उपासक, उपासिका संघ एवं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा, राजगढ़, रायसेन आदि जिलों से सामाजिक कार्यकर्ताओं की गरिमामई उपस्थिति अत्यंत शोभनीय रही। डॉ अंबेडकर मंगल मैत्री बौद्ध विहार के उद्घाटन कार्यक्रम में

भोजन दान भी किया गया जिसमें ग्रामवासियों ने बड़ चढ़ कर भाग लिया। मंगल मैत्री बौद्ध विहार के प्रमुख पूज्य भंते जगदीश आनंद जी ने युवा प्रदेश के प्रदेश ब्यूरो अतर सिंह भारतीय को बताया कि इस मोनेस्ट्री केंद्र के माध्यम से आम जनता को सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे लोगों में सद्भाव पैदा होगा। डॉ भीमराव अंबेडकर समिति नवीन छावनी पठार के विशेष सहयोग से निर्मित किए जा रहे इस बौद्ध विहार के उद्घाटन कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार अहिरवार ने आभार व्यक्त कर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रदेश से चयनित विद्यार्थी और शालाओं को मिला सम्मान

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल
मध्यप्रदेश

प्रदेश की शालाओं में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन के लिए संचालित शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और शालाओं को राज्य स्तर पर सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राज्य शिक्षा केन्द्र में समारोह में कक्षावार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के चयनित 11 विद्यार्थियों व 11 शालाओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम का संचालन सहयोगी संस्था एडसिल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कि विगत वर्ष 3 जुलाई 2025 से प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को सुदृढ़ करना था। इसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के लगभग 12 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। विद्यार्थियों एवं विद्यालयों का चयन जिला-वार कवरेज, विद्यालयों के प्रकार और बालक-बालिका अनुपात आदि मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया। बेसलाइन एवं एंडलाइन मूल्यांकन के



माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का वैज्ञानिक आकलन एवं प्रगति मापन सुनिश्चित किया गया। शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 8वीं की 5,020 चयनित शालाओं के 5,99,143 विद्यार्थियों और कक्षा 9वीं से 12वीं की 4,528 चयनित शालाओं के 6,00,000 विद्यार्थियों का बेसलाइन मूल्यांकन कराया गया। शिक्षकों के लिए विषयगत ज्ञान एवं शिक्षण-कौशल उन्नयन के लिए एआई पर ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 8वीं के कुल 10,026 और कक्षा 9वीं से 12वीं के कुल 8,475 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विद्यार्थियों की अध्ययनशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के ऑनलाइन सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए गए। साथ ही,

बच्चों की पढ़ाई में आए गैप को दूर करने के लिए कमजोर छात्रों को सिखाने वाली विशेष सामग्री किताबें, नोट्स तैयार कर वितरित की गईं। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर चयनित विद्यार्थियों के लिए भ्रमण एवं एक्सपोज़र विजिट का आयोजन कर खुद देखकर या करके सीखने के अवसर उपलब्ध कराये गए। इस कार्यक्रम से आधारभूत एवं विषयगत दक्षताओं के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर कक्षा अध्यापन, छात्र सहभागिता एवं अधिगम प्रेरणा में वृद्धि के साथ ही तकनीक आधारित शैक्षणिक मॉनिटरिंग व्यवस्था में लाभ होगा। समारोह में प्रदेश में संचालित शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया गया।

जिले में 'स्किल गैप एनालिसिस' कर उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार होंगे प्रशिक्षित युवा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल
मध्यप्रदेश

जिला पंचायत भोपाल की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी ने कहा है कि कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग तक उनका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के अवसरों की जानकारी अंतिम छोर तक पहुंचाकर अधिक से अधिक युवाओं, विशेषकर महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। इला तिवारी मंगलवार को शासकीय सभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोविंदपुरा में आयोजित जिला कौशल समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में जिले में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों, रोजगारोन्मुखी योजनाओं तथा हितग्राही मूलक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए भावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आगामी 12 जून को यूएन वूमेन के 'वी स्टेम' कार्यक्रम के अंतर्गत 100 से अधिक पदों तथा 16 जून को ट्राइडेंट बुधनी द्वारा आयोजित 500 से अधिक पदों वाली मेगा महिला-केंद्रित प्लेसमेंट ड्राइव में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित



करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं तथा आठवीं, दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण बालिकाओं एवं महिलाओं को इन अवसरों से जोड़ने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। जनकल्याण शिविरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में भी कौशल विकास योजनाओं एवं आईटीआई प्रवेश संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आईटीआई में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समग्र प्रोफाइल

तैयार करने के लिए 'हर्ष पोर्टल' पर उनकी जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम तथा प्रधानमंत्री इंटरनेट स्कीम के तहत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लंबित ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं हितग्राहियों को समय पर ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्राचार्य आईटीआई ने बताया कि संस्थान द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में कई नवाचार किए जा रहे हैं। थिंक गैस के साथ हुए एमओयू के तहत 9 एवं 10 जून को प्रशिक्षणदाताओं के लिए दो दिवसीय टीओटी कार्यक्रम

आयोजित किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत 'ड्रोन तकनीशियन' तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 'सोलर तकनीशियन' प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 250 प्रशिक्षणार्थियों को एनआईईएसबीयूडडी के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के तहत नगर निगम के रीसाइक्लिंग प्लांट का भ्रमण भी कराया गया। जिले के अधिक से अधिक प्रतिभाशाली युवाओं को वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए तैयार कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। बैठक में जिले की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को संयुक्त रूप से 'स्किल गैप एनालिसिस' कराने के निर्देश दिए गए। इस सर्वेक्षण के माध्यम से जिले में कुशल मानव संसाधन की मांग और उपलब्धता का आकलन कर उद्योगों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध कराया जाएगा।

शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में विश्व पर्यावरण दिवस पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित



पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम। में शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज तथा विधि विभागाध्यक्ष शिवाकांत मोर्य के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं इको क्लब के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डा महेंद्र कुमार पटेल द्वारा विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों को बीजों के अंकुरण, पौध तैयार करने तथा वैज्ञानिक विधि से रोपण करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में पौधारोपण के महत्व तथा वृक्षों के संरक्षण की मांग और उपलब्धता का आकलन कर उद्योगों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध कराया जाएगा।

महाविद्यालय द्वारा गोद ली गई ग्राम पंचायत बुधवाड़ा में पौधारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिवाकांत मोर्य, डॉ. अभिषेक सिंह, राजदीप सिंह भदौरिया, डॉ. ओम शर्मा सहित महाविद्यालय के अन्य स्टाफ सदस्यों एवं स्वयंसेवकों ने अशोक के पौधे रोपे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण करने का वचन दिया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयंसेवकों में पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करना तथा प्रकृति संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना रहा।

मंत्रालय में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक आयोजित

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। उच्च शिक्षा मंत्री ने संस्थान के शैक्षणिक, शोध, छात्र कल्याण एवं अधोसंरचनात्मक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों के अनुरूप तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने जापान सहित भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों वाले देशों की भाषाओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल देते हुए कहा कि इससे युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे तथा वे विदेशों में प्रभावी संवाद स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने संस्थान को इस दिशा में नवाचारपूर्ण पहल करने के निर्देश दिए। छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए परिसर में सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं के लिए स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्याप्त



शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया तथा कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधायुक्त परिसर भी उतना ही आवश्यक है। संस्थान परिसर में वृहद स्तर पर नीम, बरगद, पीपल, जामुन एवं आम जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों के

रोपण के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान के हरित वसुंधरा क्लब द्वारा लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं रोपण के संकल्प की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अनुकरणीय बताया। संस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत शोधपत्रों के

संकलन एवं संस्थान के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग अनुपम राजन ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में संस्थान के वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट

12 करोड़ 86 लाख 3 हजार 503 रुपये को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही संस्थान के प्रत्येक संकाय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को संचालक पदक प्रदान किए जाने तथा सामान्य परिषद के अध्यक्ष के नाम से विशेष पदक स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। परिषद ने प्रत्येक संकाय के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षणिक शुल्क में राहत प्रदान करने के प्रस्ताव को भी सहर्ष स्वीकृति दी। उच्च स्तरीय शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फोरियर इन्फ्रेड स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण के क्रय के लिये 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। साथ ही विभिन्न स्तरों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को भी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। संस्थान के संचालक डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल द्वारा सामान्य परिषद को अवगत कराया गया कि वर्ष 2026 में भारतीय वाणिज्य परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में संस्थान द्वारा सेज विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर परिषद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी सहमति प्रदान की।

डॉ कैलाशनाथ काटजू मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में विशाल गर्भवती जांच शिविर

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

डॉ. कैलाशनाथ काटजू मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान भोपाल की नोडल एवं सेंटर हेड डॉ. रचना दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशाल गर्भवती जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं ने पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्त परीक्षण, रक्तचाप जांच, हीमोग्लोबिन जांच, सोनोग्राफी परामर्श एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह का लाभ प्राप्त किया डॉ. रचना दुबे ने मरीजों को सुरक्षित मातृत्व, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण एवं गर्भावस्था के दौरान आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 एवं 25 तारीख को डॉ. कैलाशनाथ काटजू मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान भोपाल में विशेष गर्भवती जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की समग्र जांच एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। उन्होंने



बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान संस्थान की ओर से गर्भवती महिलाओं को शीतल

पेय एवं आवश्यक पोषण संबंधी सामग्री भी प्रदान की गई, जिससे महिलाओं में उत्साह एवं जागरूकता का सकारात्मक संदेश देखने को मिला। उपस्थित चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच कराने एवं संस्थागत प्रसव को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

22 अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की संयुक्त टीम ने की कार्यवाही



कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

पवित्र नगरी अमरकंटक को अतिक्रमण मुक्त, सुव्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद अमरकंटक द्वारा बुधवार को अतिक्रमण विरोधी विशेष अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग, नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने वार्ड क्रमांक 14 में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की। अभियान के दौरान शासकीय भूमि पर किए गए कुल 22 अवैध अतिक्रमणों को हटाकर भूमि को मुक्त कराया गया। इनमें 15 बाड़ियां, 4 झोपड़ियां तथा 3 कच्चे मकान शामिल थे। प्रशासन द्वारा जेसीबी एवं अन्य मशीनों की सहायता से अतिक्रमणों को हटाते हुए भूमि को अपने

कब्जे में लिया गया। कार्यवाही के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। अधिकारियों ने बताया कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिले में शासकीय भूमि के संरक्षण एवं नगरों के सुनियोजित विकास के लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न करें तथा नगर के स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित विकास में सहयोग प्रदान करें।